केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मोटर साईकिल/कार हेतु ऋण

3336. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मोटर साईकल/कार खरीदने के लिए ऋण के रूप में अधिकतम कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है और यह सीमा किस वर्ष में निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि जिस वर्ष में यह अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी उस समय बाजार में मोटर साईकल/कार की कीमत कितनी थी और इस समय कितनी है यदि हां, तो कीमतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन बढ़ी हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए मोटर साईकिल/कार खरीदने के लिए ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर विचार किया है, यदि हां तो क्या निर्णय लिया गया है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सीमा को बढ़ाने का निर्णय लेगी ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोटर साईकिल मोटर कार खीदने के लिए स्वीकार्य अग्रिम की अधिकतम राशि निम्नलिखित है :—

(i) मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम : 1500 रु. प्रतिमाह और उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी 13,000 रु. तक अथवा 8 माह का मूल वेतन अथवा वाहन के प्रत्याशित मूल्य के बराबर अग्रिम राशि, इनमें जो भी कम हो, प्राप्त करने के पात्र हैं दूसरी बार अथवा बाद के किन्हीं मौकों पर अग्रिम की राशि घटाकर 10000/—रु० तक अथवा 6 माह के मूल वेतन अथवा वाहन के प्रत्याशित मूल्य के बराबर इनमें जो भी कम हो, कर दी जाती है ।

(ii) मोटर कार अग्रिम 3500/—रु० प्रतिमाह अथवा उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचायी 80,000/—रु० तक अग्रिम अथवा संबंधित सरकारी कर्मचारी के 16 महीने के मूल वेतन के बराबर अथवा मोटर कार के प्रत्याशित मूल्य के बराबर राशि, इनमें से जो भी कम हो, पाने के लिए पात्र है । दूसरी बार अथवा बाद में किसी और मौके पर अग्रिम की यह राशि घटाकर 75,000/—रु० अथवा सरकारी कर्मचारी के 16 महीनों के मूल वेतन अथवा मोटर कार के प्रत्याशित मूल्य के बराबर तक, इन में जो भी कम हो, कर दी जाती है ।

उपर्युक्त सीमाएं 1987 में निर्धारित की गयी थीं ।

उपर्युक्त के अलावा सरकारी कर्मचारियों को यह भी विकल्प प्राप्त है कि वे मोटर साईकल/स्कूटर खरीदने के लिए 8000/—रु० तक अथवा मोटर कार खरीद के लिए 50,000/—रु० तक की राशि अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में से अग्रिम ले सकते है अथवा निकलवा सकते है, ताकि वे अग्रिम राशि तथा वार्डन की वास्तविक लागत के बीच होने वाले अंतर को पूरा कर सकें ।

(ख) और (ग) हालांकि मोटर साइकिलों और कारों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तथापि संसाधनों की कमी की वजह से मोटर साइकिल मोटर कार अग्रिम की सीमा में वृद्धि करना फिलहाल संभव नहीं है ।

Representation by Primary Agricultural Cooperative Society to Andhra Bank

3337. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Andhra Bank has not reacted to diverse representations of Primary Agricultural Cooperative Societies in West Godavari disrict, Andhra Pradesh for loan write-offs;

(b) what reasons have been advanced by Andhra Bank in the case of Krishnaraopeta Primary Agricultural Cooperative Society in West Godavari district, Andhra Pradesh;

(c) whether it is a faot that this particular Cooperative Society has fulfilled all requirements, including requisite certificates from the District Collector; and

(d) whether suitable directions will be given to Andhra Bank to review the whole issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY : (a) to (d) Andhra Bank, which is assigned with the Lead Bank responsibility in West Godavari District of Andhra Pradesh has reported that it had received representations from Primary Agricultural Cooperative Societies in the District, including from the Krishnaraopet Society, for providing debt relief. The bank has reported that it had constituted special teams at respective blocks in the District to identify the eligible borrowers and receive claims from participating banks in the area to determine their eligibility, as per guidelines framed by Reserve Bank of India/Government. There were no procedural errors or other lacuna noticed during; the course of providing debt relief to all the eligible borrowers in the West Godavari district. As per the guidelines, the eligible borrower must have suffered atleast two bad crop years (either consecutively or alternatively) and the said borrower should not be a wilful defaulter to the Bank. In so far as the Krishnaraopet PACS, the annewari was available for the year 1988 only and hence was treated as on]y one Annawari. The other crop years prior to or after 1988 were not bad crop years and, therefore, the members of the Society were not eligible for debt relief, and thus, the Society had not fulfilled the eligibility requirements.

Functioning of IFO in A. P.

' 3338. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) what has been the role of IFCI ., in financial industrial activity in Andhra Pradesh;

(b) whether it is a fact that IFCI has no financial units in Andhra Pradesh; and

(c) the steps proposed to review the functioning of IFCI?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY : (a) The Industrial Finance Corporation of India Ltd. (IFCI) has reported that it provide medium and long term credits to eligible industrial concerns, which meet the eligibility criteria for obtaining financial assistance from IFCI, incorporated and registered in India in corporate or cooperative sector, engaged in manufacturing activities or service sector, IFCI is an all-India Financial Institution and its spectrum of activities covers all States and Union Territories including Andhra Pradesh.

(b) and (c) No, Sir. IFCI since its inception in 1948 to 28th February, 1995 has provided financial assistant* aggregating Rs. 1850.47 crores to 432 industrial projects located/to be located in Andhra Pradesh and its percentage share worked out to 7.9 per cent of th< total assistance sanctioned by IFCI to all the States.

Representation from Primary Agncultu ral Cooperative Credit Society *in* Andhra Pradesh

3339. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FINANCS be pleased to state:

(a) whether Banking Division has re ceived any representation in 1994-9 from Primary Agricultural Cooperate Credit Society in Andhra Pradesh regarc ing grievances concerning nationalise banks, like Andhra Bank;

(b) whether it is a fact that the: has been no response from Banking Div sion to numerous representations fro Krishnaraopeta Cooperative Credit S clety in West Godavari district of A dhra Pradesh;